जल संसाधन विभाग
बजट घोषणा वर्ष 2017-18

क्रसं.	घोषणा	क्रियान्विति रिपोर्ट
1	**बिन्दु संख्या–141.0.0** जल संसाधन विभाग के लिए आगामी वर्ष में 3 हजार 313 करोड़ 8 लाख रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है, जो कि वर्ष 2016-17 के संशोधित अनुमान से 11.14 प्रतिशत अधिक है।	उक्त घोषणा के अन्तर्गत प्रावधित बजट राशि में से जल संसाधन विभाग हेतु राशि रूपयें 201452.00 लाख का बजट प्रावधान वर्ष 2017–18 हेतु स्वीकृत हैं। इसमें से प्रथम त्रैमास हेतु 25 प्रतिशत तक का बजट/साख सीमा वित विभाग से प्राप्त हो चुकी है जिसका उपयोग प्रगतिरत/प्रस्तावित परियोजनाओं पर किया जा रहा है। **Task Started But Not Completed**
2	**बिन्दु संख्या–138.0.0** धौलपुर लिफ्ट परियोजना की आवश्यकता पिछले कई दशकों से महसूस की जा रही है। राज्य सरकार के प्रयास से लंबे समय से लंबित clearance अब प्राप्त करली गई है। आगामी वर्ष 800 करोड़ रुपये की इस परियोजना पर कार्य प्रारंभ किया जायेगा , जिससे धौलपुर के 114 तथा राजाखेड़ा के 62 कुल 176 गाँवों के 34 हजार हैक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध हो सकेगी।	प्रस्तावित धौलपुर येाजना में 0.3 हैक्टेयर जमीन घडियाल अभ्यारण मे आती है। NBWL की दिनांक 02.06.2015 को हुई 34वीं बैठक (minutes of meeting vide F-No6-48/2015WL Dated 24.06.2015) मे धौलपुर सिंचाई परियोजना के अन्तर्गत 0.3 हैक्टेयर घडियाल अभियारण की भूमि के प्रत्यावर्तन हेतु 22वीं स्अेंडिग कमेटी की बैठक मे दी गई सैदान्तिक स्वीकृति को confirm किया है। सीईसी में दिनांक 28. 09.2015 के प्रकरण की सुनवाई में NBWL की उपरोक्त minutes of meeting को स्वीकृत कर लिया गया है। सीईसी द्वारा दिनांक 27.11. 2015 के द्वारा सशर्त स्वीकृति दी गई है। प्रकरण में परियोजना को क्रियान्वित किए जाने हेतु आगामी कार्यवाही निम्न प्रकार की जा रही है। 1. परियेाजना में आरक्षित वन क्षेत्र की 7.2 हैक्टेयर भूमि की अनाप्ति प्राप्त किये जाने के सम्बन्ध में विभागीय अधिकारियों द्वारा कार्यवाही की जा रही है । 2. परियोजना की प्रशासनिक स्वीकृति कराये जाने हेतु तखमीना राशि 782.00 करोड का तैयार किया गया है। 3. परियोजना की लाभ लागत अनुपात 1. 52:1 का निर्धारण कर दिया गया है। 4. परियोजना हेतु वित्तीय संसाधन उपलब्ध करवाने की कार्यावाही की जा रही है। **– Task Sanctioned But Not Started**
3	**बिन्दु संख्या–137.0.0** बूँदी जिले में वर्ष 2010 में क्षतिग्रस्त हुये	1. केन्द्रीय जल आयोग एवं नई दिल्ली द्वारा बांध की मृदा निरीक्षण हेतु मृदा नमूने

क्रसं.	घोषणा	क्रियान्विति रिपोर्ट
	गरड़दा बाँध का पुनर्निर्माण नहीं होने के कारण लगभग 9 हजार हैक्टेयर क्षेत्र के किसानों को मिलने वाला लाभ कई वर्षों से लंबित है। आगामी वर्ष इस क्षतिग्रस्त बाँध का निर्माण कार्य प्रारंभ किया जायेगा।	उनके द्वारा चयनित स्थानो पर दिनांक 28. 02.2017 से 01.03.2017 को ले लिये गये है तथा उक्त नमूनो की परीक्षण रिपोर्ट दिनांक 28.03.2017 को प्राप्त हो गई है। जिसे केन्द्रीय जल आयोग, नई दिल्ली को भिजवा दिया गया है। 2. केन्द्रीय जल आयोग द्वारा प्रस्तावित बांध के रेमेडियल मेजर कार्य के निर्माण हेतु डिजाईन , हाइड्रोलोजी आदि करवाकर ड्राईन्गास प्राप्त करने का कार्य दिनांक 15. 07.2017 तक प्रस्तावित। 3. प्राप्त ड्राईन्गास के आधार पर बांध के प्रस्तावित निर्माण कार्य का तखमीना तैयार करना दिनांक 15.09.2017 तक प्रस्तावित। 4. सम्पूर्ण निविदा प्रकिया दिनांक 20.11.2017 तक। 5. बांध का पुनरूद्वार/पुर्ननिर्माण कार्य पूर्ण करना दिनांक 31.03.2021 तक प्रस्तावित। **Task Sanctioned But Not Started**
4	**बिन्दु संख्या–136.0.0** परवन बहुद्देश्यीय सिंचाई परियोजना तथा Eastern Rajasthan Canal Project (ERCP)को राष्ट्रीय महत्व की परियोजना घोषित करने हेतु भारत सरकार के समक्ष प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये हैं।	उक्त दोनों परियोजनाओं को ''राष्ट्रीय महत्व की परियोजना'' घोषित करने हेतु सचिव, जल संसाधन मंत्रालय, भारत सरकार को निवेदन किया है जिसकी स्वीकृति अपेक्षित है। **– Task Started But Not Completed**
5	**बिन्दु संख्या–135.0.0** बारां, झालावाड़ एवं कोटा जिले के लगभग 2 लाख हैक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा एवं 820 गाँवों में पेयजल उपलब्ध कराने के लिए परवन बहुद्देश्यीय सिंचाई परियोजना हेतु आवश्यक clearance प्राप्त कर बाँध के निर्माण हेतु टेंडर आमंत्रित किये गये हैं। वित्तीय वर्ष 2016-17 में इस परियोजना पर 700 करोड़ रुपये का व्यय किया गया है। आगामी वर्ष में इस हेतु एक हजार करोड़ रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है।	दिनांक 18.09.2015 द्वारा निविदा आमंत्रित कर ली गई है, कार्य की तकनिकी बिड दिनांक 28.04.2017 को खोली जा चुकी है जिसका परीक्षण किया जा रहा है। **– Task Sanctioned But Not Started**
6	**बिन्दु संख्या–134.0.0** चंबल बेसिन के पानी को राज्य के अन्य जिलों में पहुँचाने के लिए Eastern Rajasthan Canal Project (ERCP)की	चम्बल बेसिन की पार्वती नदी एवं काली सिंध नदी को जोडने एवं नहर द्वारा पानी को धौलपुर पहुंचाने की परियोजना 'Eastern Rajasthan Canal Project" की डीपीआर बनाने हेतु प्रशासनिक एवं तकनिकी स्वीकृति पत्र क्रमांक 1653–54 दिनांक

क्रसं.	घोषणा	क्रियान्विति रिपोर्ट
	DPR तैयार करने का कार्य प्रगति पर है। इससे राज्य के 13 जिलों (झालावाड़, बारां, कोटा, बूंदी, सवाईमाधोपुर, अजमेर, टोंक, जयपुर, करौली, अलवर, भरतपुर, दौसा व धौलपुर) की पेयजल एवं सिंचाई की दीर्घकालीन आवश्यकता पूरी हो सकेगी।	31 मार्च 2016 के द्वारा राशि रूपयें 22.07 करोड की जारी की गई है । वेपकोस को कार्यादेश दिनांक 05.04.2016 को जारी किये जा चुके है। योजना का Tentative alignment स्वीकृत कर लिया गया है। डीपीआर बनाने का कार्य प्रगतिरत है। वेपकोस. द्वारा प्रस्तुत फिजिबिलिटी रिपोर्ट को केन्द्रीय जल आयोग को प्रेषित किया गया है। ड्राफ्ट डीपीआर दिनांक 30.05.2017 से पूर्व प्राप्त होना प्रस्तावित है। **Task Started But Not Completed**
7	बिन्दु संख्या–132.0.0 Four Water Concept के तहत 320 micro irrigation tank, 48 check Dams एवं 50 micro storage tank के कार्य प्रारंभ किये गये हैं , जिनमें से जनवरी 2017 तक 269 कार्य पूर्ण हो चुके हैं। अब तक 747 करोड़ के स्वीकृत कार्यों पर 366 करोड़ रुपये व्यय किया जा चुका है। ये कार्य आगामी वित्तीय वर्ष में पूर्ण कर लिये जायेंगे।	Four Water Concept के तहत दिनांक 31.03. 2017 तक 298 कार्य पूर्ण कर लिये गये है। जिन पर 389.59 करोड रू. व्यय किये जा चुके है। ष्षेष कार्य प्रगति पर है। जो इसी वित्तीय वर्ष में पूर्ण कर लिये जायेगे। **Task Started But Not Completed**
8	बिन्दु संख्या–131.0.0 हरिके बेराज के गेटों को बदलने , बेराज एवं नहर की डीसिल्टिंग , जीर्णोद्धार तथा माधोपुर व्यास लिंक की विशेष मरम्मत हेतु 66 करोड़ रुपये वर्ष 2016-17 में पंजाब सरकार को हस्तांतरित किये गये हैं , ताकि नहर बंदी के दौरान इन महत्वपूर्ण कार्यों को पूर्ण कर प्रदेश के हिस्से का अधिक से अधिक जल प्राप्त किया जा सके।	हरिके बैराज के गेटो के अपस्ट्रीन पौण्डस की सिल्ट क्लीयरेन्स एवं इन्दिरा गांधी फीडर व सरहिन्द फीडर के कौमन बैक की रिपेयर इत्यादि के कार्य हरिके बैराज पर दिनांक 27.03.17 से 20.04.17 तक क्लोजर अवधि में करवाये गये है। माधोपुर ब्यास लिंक के रिपेयर के कार्य पंजाब द्वारा अभी प्रारम्भ नही किये गये है। इस कार्य को करवाये जाने के लिये क्लोजर की आवश्यकता नही है। **Task Started But Not Completed**
9	बिन्दु संख्या–127.01.0 आगामी दो वर्षों में कोटा , सिरोही, बूँदी, भीलवाड़ा, उदयपुर, बाँसवाड़ा, टोंक, चित्तौड़गढ़, सीकर, सवाईमाधोपुर एवं अजमेर जिले की 36 लघु सिंचाई परियोजनाओं के जीर्णोद्धार का कार्य 56 करोड़ 70 लाख रुपये की लागत से करवाया जायेगा।	RRR (PMKSY) के तहत प्रेषित 36 डीपीआर का अनुमोदन केन्द्र सरकार द्वारा गठित राज्य स्तरीय स्वीकृतदाता (कृषि विभाग) से दिनांक 15.02.2017 को अनुमोदन किया जा चुका है। **– Task Sanctioned But Not Started**

इंदिरा गांधी नहर विभाग

बजट घोषणा वर्ष 2017-18

क्रसं.	घोषणा	क्रियान्विति रिपोर्ट
1	बिन्दु संख्या–140.0.0 चौधरी कुंभाराम आर्य (साहवा) लिफ्ट सहित 6 लिफ्ट स्कीमों के 3 लाख 20 हजार हैक्टेयर सिंचित क्षेत्र को फव्वारा पद्धत्ति से सिंचाई सुविधा उपलब्ध करवाने हेतु एक हजार 658 करोड़ रुपये की परियोजना भारत सरकार द्वारा स्वीकृत की गई है तथा इसके प्रभावी क्रियान्वयन के लिए राज्य सरकार कटिबद्ध है।	इंदिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र की द्वितीय चरण की 6 लिफ्ट परियोजनाओं के 3.20 लाख हैक्टेयर सिंचित क्षेत्र में फव्वारा कार्यो को (50 प्रतिशत केन्द्रीय सहायता हेतु) सीएडी, डब्ल्यूएम कार्यक्रम के अन्तर्गत सम्मिलित करने की स्वीकृति केन्द्र सरकार के पत्र दिनांक 18.03.2016 द्वारा जारी कर दी गई है। उपरोक्त 6 लिफ्ट योजनाओं में चौधरी कुम्भाराम आर्य योजना की 3 नहरों में रू. 52.69 करोड के कार्य आवंटित कर प्रारम्भ कर दिये गये है। इसके अतिरिक्त कुम्भाराम आर्य, डॉ करणी सिंह एवं पन्नालाल बारूपाल लिफ्ट योजनाओं की लगभग 1.56 लाख हैक्टेयर सिंचित क्षेत्र में लगभग रू. 707 करोड अनुमानित लागत के 4 अन्य कार्य आवंटित कर कार्यादेष जारी कर दिये गये है। जिन्हें सितम्बर, 2018 तक पूर्ण करवाया जाना प्रस्तावित है। **– Task Started But Not Completed**

सिंचित क्षेत्र विकास विभाग

बजट घोषणा वर्ष 2017-18

क्रसं.	घोषणा	कियान्विति रिपोर्ट
1	**बिन्दु संख्या–128.0.0** चंबल नहर की वितरण प्रणाली में सुधार हेतु गत् तीन वर्षों में 115 करोड़ रुपये व्यय किये गये हैं, जिसे चालू रखते हुए आगामी वर्ष में भी 125 करोड़ रुपये की लागत से सुधार कार्य करवाये जायेंगे।	विगत तीन वर्षो में चम्बल नहर की वितरण प्रणाली में सुधार कार्य हेतु सात पैकेज के कार्यादेश राशि रूपये 282.59 करोड़ के जारी कर दिये गये थे, जिनके विरूद्ध मार्च 2017 तक राशि रूपये 115.00 करोड व्यय किये जा चुके है तथा वर्तमान में कार्य प्रगतिरत है। उपरोक्त के अलावा चम्बल नहर की वितरण प्रणाली में सुधार कार्य हेतु दांयी एवं बांई मुख्य नहर की वितरिकाओं के सात पैकेज के कार्यादेश राशि रूपये 394.80 करोड के जारी कर दिये गये है तथा इस वित्तीय वर्ष 2017-18 में राशि रूपये 125 करोड़ की लागत से सुधार कार्य करवाये जायेंगे। कार्य दिनांक 31.03.2018 तक पूर्ण किये जाने प्रस्तावित है। **– Task Started But Not Completed**
2	**133.01.0 (2017-2018)** **आगामी वित्तीय वर्ष में माही, पांचना, चवली, छापी, गंभीरी, जवाई, भाखड़ा फेज-2 एवं गंग नहर फेज-3 के नहर प्रणाली क्षेत्रों में पक्के खालों का निर्माण प्रारंभ करवाया जायेगा, जिससे 3 लाख 56 हजार हैक्टेयर क्षेत्र में किसानों को सिंचाई की बेहतर सुविधा उपलब्ध हो सकेगी।**	**माही, पांचना, चवली, छापी, गंभीरी, जवाई, भाखड़ा फेज-2 एवं गंग नहर फेज-3 के नहर प्रणाली क्षेत्रों में पक्के खालों का निर्माण की स्वीकृति State Level Sanctioning Committee (SLSC) द्वारा कर दी गई है तथा इन परियोजनाओं की डी.पी.आर परीक्षण एवं स्वीकृति हेतु केन्द्रीय जल आयोग क्षेत्रीय कार्यालय जयपुर को प्रस्तुत कर दी गई है। भारत सरकार की स्वीकृति प्राप्त होने के उपरान्त कार्य प्रारम्भ किये जा सकेंगे।** कार्य दिनांक 31.03.2018 तक पूर्ण किये जाने प्रस्तावित है। **– Task Sanctioned But Not Started**